

बाजरे की उपज 'भावांतर भरपाई योजना' में शामिल

चर्चा में क्यों?

28 सितंबर, 2021 को हरियाणा सरकार ने इस खरीफ सीजन से बाजरे की उपज को भी 'भावांतर भरपाई योजना' में शामिल करने का नरिणय लिया है। इससे पहले, हरियाणा में बागवानी फसलों के लिये भी 'भावांतर भरपाई योजना' लागू की जा चुकी है।

प्रमुख बदि

- यह योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस योजना में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बाजरे की खरीद के बारे में नमिन्लखिति नरिणय लिये गए हैं-
 - बाजरे के औसत बाजार भाव व एम.एस.पी. के अंतर को भावांतर मानते हुए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत कसिानों की फसल के सत्यापन उपरांत सही पाए गए कसिानों को औसतन उपज पर 600 रुपए प्रति क्वटिल भावांतर दिया जाएगा।
 - बाजरे के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए प्रति क्वटिल नरिधारति किया गया है, जबकि पिछोसी राज्यों- राजस्थान और पंजाब में इस बार भी बाजरे का कोई एम.एस.पी. घोषति नहीं किया गया है और लगता है कि वै पहले की तरह इस बार भी बाजरे की खरीद नहीं करेंगे।
 - ये हरियाणा प्रदेश के उन कसिानों का ही बाजरा खरीदने के लिये भावांतर पर भरपाई करने का नरिणय लिया गया है, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उपज भाव को मेनटेन करने के लिये बाजार भाव पर 25 प्रतिशत उपज सरकारी एजेंसी खरीदेगी।
 - खरीफ सीजन 2021 में बाजरे के लिये 2 लाख 71 हजार कसिानों ने 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। इसमें से लगभग 8 लाख 65 हजार एकड़ भूमिका सत्यापन हुआ है। खरीद शुरू होते ही कसिानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए प्रति क्वटिल भावांतर औसत उपज के अनुसार भुगतान कर दिया जाएगा।
 - इस सीजन में सरकार पाँच फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। खरीफ फसलों में बाजरे के अतिरिक्त मूँग, मक्का और धान की खरीद 1 अक्टूबर से तथा मूँगफली की खरीद 1 नवंबर से शुरू होगी।
 - इसके अलावा, राज्य सरकार पहली बार अरहर, उड़द और तिलि की खरीद भी करने जा रही है, जो 1 दसिंबर से शुरू होगी।
 - कसिानों को बाजरे के स्थान पर तलिहन और दलहन, जैसे- मूँग, अरहर, अरंडी, मूँगफली जैसी फसलें उगाने के लिये प्रोत्साहति किया जा रहा है। बाजरे के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की बजाई करने और कुल बाजरे का उत्पादन कम करने वाले कसिानों को ही 4,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।
 - प्रदेश में बाजरे की खरीद के लिये 86, मूँग की खरीद के लिये 38, मक्का के लिये 19 तथा मूँगफली की खरीद के लिये 7 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। धान की खरीद के लिये भी 199 खरीद केंद्र बनाए गए हैं।